

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8097/2021 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.184 ha. (35008 cum per annum) (Khasra No. 1147, 1148), Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1147, 1148), Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.184 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 3806 dated: 23/12/2020 has reported that there are 02 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine total area of 6.058 ha., including this mine.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 477वीं दिनांक 30/01/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 05 बबूल के पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से 03 पेड़ काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण भाग से 20 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी है जो दूसरी खदान तक पहुँच मार्ग है तथा एक अतिरिक्त कच्चा मार्ग उसी दिशा में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो की स्वास्थ्य जाँच, वृक्षारोपण एवं मिनरल इवेक्वेशन रोड पर जल छिड़काव के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-35,008 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 09.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.45 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :—

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
01	स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में एक बार नियमित स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जायेगी।	40,000 /—
02	ग्राम प्रकाश बम्हौरी के आंगनबाडी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिये लकड़ी के खिलौनों का वितरण किया जाएगा।	60,000 /—
03	सड़क के रखरखाव की राशि ईएमपी में शामिल है।	
(आगामी एक वर्ष तक) योग		1,00,000 /—

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, बबूल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम उचाई 01 मीटर)	आम, नीम, पीपल, चिरौल, करंज, एवं महुआ अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	500
3	प्रकाश बम्हौरी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, मुनगा, आम, अमरुद, कठल अन्य फलदार प्रजातियां।	485
4	प्रकाश बम्हौरी के विद्यालय में	कदंब, अमलतास, सीता अशोक, नीम, कचनार, गुलमोहर अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ।	15
कुल			1600

2. Case No. – 6715/2019 Ms. Veena Chaturvedi, M.M.Choubey ward, Behind Chaturvedi Complex, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Limestone Quarry in an area of 2.65 ha. (50,000 tonne per annum) (Khasra No. 76), Village - Rajarwara, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP. EIA Consultant - M/s. P&M Solutions, NOIDA, (U.P.).

This is case of Limestone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 76), Village - Rajarwara, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, (MP) 2.65 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 415वीं दिनांक 07/01/2020 एवं 523वीं दिनांक 28/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान का क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है। तत्संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2013-16 के दौरान इस क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह माईनिंग लीज पूर्व में श्री उमेशनाथ चतुर्वेदी को 3.31 हे. क्षेत्रफल, 20 वर्ष हेतु दिनांक 07/12/93 को आवंटित हुई थी। अचानक लीजी का निधन वर्ष 2006 में हो जाने के कारण इसके कानूनी हकदार अधिकार उनकी पत्नी को श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी को दिनांक 27/09/11 को प्राप्त हुए। तत्पश्चात् राज्य शासन ने एलओआई 2.902 हे. क्षेत्र हेतु दिनांक 08/07/15 को जारी की गई, जिसके अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टॉर दिनांक 08/07/15 को प्राप्त किया गया। इस खदान के 50 वर्ष लीज एक्सटेंशन के दौरान खदान का क्षेत्र कमकर 2.65 हे. किया गया। इसी बीच दिनांक 03/2/18 को लीजी श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी का भी निधन हो जाने के कारण श्रीमती वीना चतुर्वेदी इसके कानूनी हकदार अधिकार हेतु राज्य शासन दिनांक 06/10/18 को जारी किया गया किंतु इस दौरान जो टॉर जारी किया गया था उसकी अवधि दिनांक 19/06/19 को समाप्त हो गई। अतः पुनः 2.65 हे. एरिया के लिए टॉर प्राप्त किया गया।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के पाया गया कि लीज क्षेत्र के उत्तरी भाग से 50 मीटर की दूरी पर रेल्वे साईडिंग कि रेल्वेलाईन निकल रही है जो इन खदानों के खनिज परिवहन हेतु बनाई गई है। खदान के पूर्व क्षेत्र में 170 मीटर पर कुछ निर्माण गतिविधियाँ दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उस ओर स्थित खदान की गारलेंड ड्रेन बनाई जा रही है। खदान क्षेत्र में पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान वर्ष 2017 से बंद है। इस कारण उसमें पानी भरा हुआ है जिसको खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पम्प के द्वारा निकाला जायेगा। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को कहा यदि खनन कार्य 2017 तक होगा तो क्या यह वायलेंशन नहीं है। तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा टॉर हेतु प्रकरण 2015 प्रस्तुत कर दिया गया था तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कि सम्मति जो 04/12/2018 तक वैध थी के आधार पर वर्ष 2017-18 तक खनन कार्य किया गया उसके पश्चात् से सभी कार्य बंद है।

परियोजना प्रस्तावक ने समिति द्वारा दिये गये अतिरिक्त टॉर (श्री मंगल सुहाने से प्राप्त दिनांक 15/9/21) के संदर्भ में सूचित किया कि स्कीम ऑफ माईनिंग प्रस्तुत न करने के कारण उनका माइन प्लॉन 27/5/21 को स्थागित किया गया था जिसको आई.बी.एम. ने 30/2/22 को रिवोक कर दिया है क्योंकि उन्होंने आई.बी.एम. से 07/12/21 को माइन प्लान अनुमोदित करा लिया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान स्कूल एवं आंगनवाड़ी में बच्चों के फर्नीचर, पंखे, कापी-किताब, रंगाई-पोताई, रजरवारा गाँव में हेंडपम्प, मजदूरों के इलाज की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ पूरे प्रकरण का तिथिवार प्रकरण तथा परियोजना प्रस्तावक का कथन कि क्यों इस प्रकरण को वायलेंशन नहीं मना जाये ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ अतिरिक्त टॉर बिंदु क्रमांक 08 का विवरण ।
- ✓ लीज वैधता का प्रमाण पत्र ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन-50,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख :-

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1	Financial aid to Anganwadi Kendra at Rajarwara for white wash, stationary, furniture & fan		@ Rs. 100,000	100,000
2	Distribution of furniture, stationary, white wash of School, & Fan in the school of Rajarwara village	1 school		55,000
3.	Handpump in Rajarwara Village	1	@45000	45000
	Total CER budget			2,00,000

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

Name	Number of plants		
	In 7.5m barrier zone	Along the transport route	On backfilled area
Mango	200	0	0
Neem	150	100	50
Khamer	100	150	100
Shisham	100	150	0
Amla	100	0	100
Chirol	50	0	0
Karanj	100	0	0
Sitafal	50	100	200
Kumbhi	100	0	0
Mahua	0	100	0
Amaltas	0	50	50
Pipal	0	100	50
Sehtoot	0	50	0
Jamun	0	100	0
Karanj	0	100	0
Putranjiva	0	100	0
Maulshree	0	100	0
Kadam	0	100	0
Arjun	0	100	0
Bel	0	0	50
Kachnar	0	0	50
Chirol	0	0	50
Achar	0	0	50
Khair	0	0	50
Kaitha	0	0	50
Total	950	1400	850

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

3. Case No 7018/2020 Shri Avinash Agarwal, PO - Jaitwara, Dist. Satna, MP – 485221 Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 11.915 ha. (30000 Tonne per annum) (Khasra No. 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 41P, 59/1 Ka, 59/1 Kha, 60, 61/1, 61/2, 61/3), Village - Gamiraha, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) EIA Consultant - M/s. P&M Solutions, NOIDA, (U.P.).

This is case of Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 41P, 59/1 Ka, 59/1 Kha, 60, 61/1, 61/2, 61/3), Village - Gamiraha, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 11.915 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 432वीं दिनांक 18/05/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण भाग से 230 मीटर एवं पूर्वी भाग से 150 मीटर व 240 मीटर दूरी पर आबादी है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूँकि खनन लेटराइट खनिज का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । इसी प्रकार खदान में 06 माहुआ पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 05 पेड़ काटे जायेंगे तथा उसके एवज में 50 अतिरिक्त पेड़ माहुआ के लगाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल रोकने के लिए परिवहन मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण एवं सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटराईट-30,000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 07.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख :-

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1	Infrastructure development			
	Construction of 1 toilet in school & Anganwadi of village Ghamiraha with water facility	1 toilet	@ Rs. 30,000	30,000
	Financial aid to Anganwadi for the programme "Poshan Aahar".		@ Rs. 50,000	50,000
	Installation of hand pump/ Drinking water supply during summer season.	1 hand pump each during 2 year		45,000
2	Sustainable Livelihood			
	Provide employment to the local villagers 20 persons (direct) & 50 indirect. The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	25	Wages will be given as per administrative rules.	
3	Health			
	Distribution of as sanitization kit (hand sanitizer, hand gloves and nose mask) and training to villagers for precautions needed in pandemic in village Ghamiraha	50 person	@ Rs. 100/set including gloves, sanitizer & mask	5000
	Heath checkup camps	1 health camp	Rs 20,000/ camp	20,000
	Total CER budget			1,50,000

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 14,500 वृक्षों का वृक्षारोपण :

Name	Number of plants			
	In barrier zone	Along the transport route	In buffer Zone at Aganwadi Kendra Kandaila and School at Birpur	On backfilled area
Neem	600	50	20	1050
Mahua	0	50	0	800
Khamer	200	100	50	110
Kachnar	150	0	50	500
Achar	0	50	100	500
Shisham	120	100	100	1000
Bel	0	100	100	300
Amaltas	0	110	100	500
Sitafal	250	50	100	2500
Khair	100	50	50	200
Chirol	150	0	50	1050
Karanj	150	0	50	850
Ber	100	0	100	500
Reetha	0	0	50	0
Kaitha	0	0	100	650
Imli	0	0	100	490
Putranjiva	0	0	50	0
Maulshree	0	0	50	0
Kadam	0	0	50	0
Total	1820	660	1270	11000
				14,500

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

4. **Case No 9166/2022 Shri Shankar Manchani, Napier Town, 88, Infront of Goodwill Complex, Dist. Jabalpur, MP - 482001 Prior Environment Clearance for Construction of "Muskan Park" (Hotel & Residential Building of House Corporation) [Total Project Area = 7544.14 sqm (0.75 ha.), Built-up Area = 34145.10 sqm] at Plot No. 7/2, 7/2-K, Napier Town, Tehsil & Dist. Jabalpur, (MP) (Cat. 8(a) Building and Construction Project) Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)**

This is case of Prior Prior Environment Clearance for Construction of "Muskan Park" (Hotel & Residential Building of House Corporation) [Total Project Area = 7544.14 sqm (0.75 ha.), Built-up Area = 34145.10 sqm] at Plot No. 7/2, 7/2-K, Napier Town, Tehsil & Dist. Jabalpur, (MP).

The case was presented by Env. Consultant Shri G. K. Mishra, M/s. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.) on behalf of PP, wherein during presentation it was observed as per Google image that PP has constructed 02 blocks and ground work was also carried out in the 03 block where apartment is proposed. Project Proponent has already constructed 4438.85 Sq.M. at site without prior Environment Clearance and is therefore, a violation of Environment Protection Act, 1986. PP submitted following salient features of the project:

Construction Status Undertaking

Total B/U Area	34,145.10 SQ.M (100%)
Till date Constructed area	4438.85 Sq.M. (13%)
Project Cost	INR 33.00Cr. (100%)
Till date Incurred cost .	INR 4.35Cr. (13.18%)

AREA STATEMENT

Total Plot Area	7,544.14 SQ.M (0.75 HECT)
Permissible Ground Coverage	30% (2,263.24 SQ.M)
Open Green	10% (756.44 SQ.M)
Services Area	1.5% (113.16 SQ.M)
Hotel Block-A Ground Coverage Area	569.00 SQ.M.
Hotel Block-B Ground Coverage Area	744.55 SQ.M.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

Residential Block-C Ground Coverage Area	949.69 SQ.M.
Total Ground Coverage Area	2,263.24 SQ.M.
Total B/U Area of Hotel Block- A FAR	3,702.28 SQ.M
Total B/U Area of Hotel Block- B FAR	3,728.00 SQ.M
Total B/U Area of Residential Block- C FAR	7,658.00 SQ.M
Non FAR	19,056.82 SQ.M
Total B/U Area	34,145.10 SQ.M

Height of the Building	30 MTS.
Lower Basement Area	4782.00 SQ.M.
Upper Basement Area	2933.00 SQ.M.
Podium – 1 Parking Area	1278.00 SQ.M.
Podium – 2 Parking Area	1278.00 SQ.M.
Casual Parking Area	400.00 SQ.M.
Far Calculation	
Total E.W.S. Area @26 Sq.M. 7 Nos	182.0 SQ.M.
Total L.I.G. Area @36 Sq.M. 4 Nos	144.0 SQ.M.
Total Area E.W.S. & L.I.G.	326.0 SQ.M.

Unit Details

Type of units	Nos.
Residential Flats Block C	60
Residential Flats Block A	11
EWS	7
LIG	4
Showrooms	4
Hotel Rooms	80
Restaurants	1
Conference Hall	1
Offices	10

During presentation as per Google image based on coordinates provided by PP, it was observed that some houses are existing in the project area PP stated that these are owner's

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

houses and proposed for demolition and dismantle material will be recycled and reused with construction material.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Some demolition works are proposed thus details of C&D wastes shall be properly addressed in the EIA report.
2. No tree falling proposed for which a written commitment shall be submitted.
3. Revised water and waste balance details shall be provided as suggested by the committee during TOR presentation.
4. Green Building concepts (Status of GRIHA rating or IGBC rating) shall be adopted and their details shall be submitted with EIA report.
5. One common convenience facility shall be provided for supporting staff.
6. Status report of construction work place so far, possession given to how many families etc.
7. Revised water requirement details for residents, hotel staffs, and for floating population etc.
8. Plantation species and their photographs.
9. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
10. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
11. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
12. Project description, its importance and the benefits.
13. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

14. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage).
15. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
16. Land acquisition status, R & R details (if any).
17. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
18. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
19. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
20. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
21. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
22. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
23. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
24. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
25. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
26. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

5. Case No 9167/2022 Shree Prashant Jain Partner, M/s Green Mining Company, R/o 108 Rajul Complex, Aaga Chowk, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 1.40 ha. (15364 Tonne per annum) (Khasra No. 17), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 17), Village - Ainthakheda, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813 दिनांक 15/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.541 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 490 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर दिशा में 325 मीटर पर बरगी नहर है। प्रश्नाधीन खदान के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिम क्षेत्र से एच.टी लाईन निकल रही है अतः उससे सेफ डिस्टेंस छोड़ा जाना होगा इसी प्रकार खदान के उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खदान से लगा हुआ एक मौसमी नाला भी निकल रहा है जिस हेतु 50 मीटर का सेट बैक तथा उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी। समिति ने पाया कि उपरोक्तानुसार सेट बैक छोड़ने के पश्चात बहुत कम ऐरिया माईनिंग हेतु उपलब्ध होगा तत्सदर्थ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनकी उत्पादन क्षमता सिर्फ 15,364 टन प्रति वर्ष है जो उपलब्ध एरिया में से निकल जायेगी। समिति ने चर्चा उपरांत यह अनुशांसा की कि परियोजना प्रस्तावक अपनी ओर से यह सुनिश्चित करले कि उपलब्ध एरिया में से वह निर्धारित उत्पादन खनन कार्य कर पायेगा तभी प्रकरण में ई.आई.ए. व लोकसुनवाई करवाये क्योंकि यदि ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के समय यह पाया गया कि उपलब्ध एरिया में खनन कार्य संभव नहीं है तो इस प्रकरण में पर्यावरण अभिस्वीकृति देने से इंकार किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

1. खदान के पूर्व दिशा में 490 मीटर पर रोड़ तथा उत्तर दिशा में 325 मीटर पर बरगी नहर है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खदान के पश्चिम क्षेत्र से एच.टी लाईन निकल रही है अतः उससे सुरक्षित दूरी छोड़ी जाना होगा तथा इसी प्रकार खदान के उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खदान से लगा हुआ एक मौसमी नाला भी निकल रहा है जिस हेतु 50 मीटर का सेट बैक तथा उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. शासकीय भूमि (यदि) का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

6. Case No 9177/2022 M/s C.P.Global Buildcon LLP, R/o 121, Chandani Chowk, Dist. Ratlam, MP - 457001 Prior Environment Clearance for Stone (M-Sand) Quarry in an area of 4.0 ha. (30070 Cum per annum) (Khasra No. 340), Village - Hedava Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 340), Village - Hedava Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 498 दिनांक 18/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 07.80 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र में यह उल्लेखित है कि खनन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-148 लगभग 500 मीटर की दूरी पर एवं कच्चा मार्ग एवं नाला 100 मीटर की दूरी पर है जबकि लीज स्वीकृति पत्र में आवेदित क्षेत्र से 8 लाईन रोड लगभग 400 मीटर, 200 मीटर पर आबादी, हाईटेंशन लाईन 200 मीटर पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 400 मीटर पर है तथा आवेदित क्षेत्र में 02 निस्तार तालाब बनाये गये हैं एवं आवेदित सर्वे नं. गौशाला हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तर दिशा में क्रमांश: 70 मीटर एवं 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार जो लीज आर्डर नं. 498 दिनांक 18/4/22 कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जिसमें लिखा है कि आवेदित क्षेत्र में 02 निस्तार के तालाब बनाये गये हैं तथा आवेदित सर्वे नं. में गौशाला हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई है अतः परियोजना प्रस्तावक कलेक्टर आफिस से यह लिखित में प्राप्त करें कि खसरा क्रमांक 340 पर खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा इसका वर्तमान उपयोग निस्तार तालाब एवं गौशाला हेतु नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 30/03/2022 अनुसार यह लीज पत्थर (एम-सेंड) हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें यांत्रिक क्रिया से एम-सेंड बनाने का प्लांट लगाया जायेगा किंतु वे यह विवरण फार्म-1 (APPENDIX- I) में उल्लेखित नहीं कर पाये हैं, अतः पुनरीक्षित फार्म-1 (APPENDIX- I) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत कर रहे ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तर दिशा में क्रमांश: 70 मीटर एवं 50 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. लीज आर्डर नं. 498 दिनांक 18/4/22 कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जिसमें लिखा है कि आवेदित क्षेत्र में 02 निस्तार के तालाब बनाये गये हैं तथा आवेदित सर्वे नं. में गौशाला हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई है अतः परियोजना प्रस्तावक कलेक्टर आफिस से यह लिखित में प्राप्त करें कि खसरा क्रमांक 340 पर खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा इसका वर्तमान उपयोग निस्तार तालाब एवं गौशाला हेतु नहीं है।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. शासकीय भूमि (यदि) का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. Case No 9180/2022 M/s C.P.Global Buildcon LLP, R/o 121, Chandani Chowk, Dist. Ratlam, MP - 457001 Prior Environment Clearance for Stone (M-Sand) Quarry in an area of 3.80 ha. (32010 Cum per annum) (Khasra No. 340, 341, 342), Village - Hedava Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 340, 341, 342), Village - Hedava Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua (MP) 3.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 624 दिनांक 27/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 8.30 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र में यह उल्लेखित है कि खनन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-148 लगभग 500 मीटर की दूरी पर एवं नाला 100 मीटर की दूरी पर है तथा लीज स्वीकृति पत्र में आवेदित क्षेत्र से नदी नाला 01 किलोमीटर, रोड़ लगभग 400 मीटर, 500 मीटर पर आबादी तथा हाईटेंशन लाईन 80 मीटर पर है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में क्रमांश: 70 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 392 दिनांक 30/03/2022 अनुसार यह लीज पत्थर (एम-सेंड) हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें यांत्रिक क्रिया से एम-सेंड बनाने का प्लांट

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

लगाया जायेगा किंतु वे यह विवरण फार्म-1 (APPENDIX- I) में उल्लेखित नहीं कर पाये हैं, अतः पुनरीक्षित फार्म-1 (APPENDIX- I) प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत कर रहे ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में कर्मांश: 70 मीटर पर प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. खनन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-148 लगभग 500 मीटर की दूरी पर एवं कच्चा मार्ग एवं नाला 100 मीटर की दूरी पर है तथा लीज स्वीकृति पत्र में आवेदित क्षेत्र से नदी नाला 01 किलोमीटर, रोड़ लगभग 400 मीटर, 500 मीटर पर आबादी तथा हाईटेंशन लाईन 80 मीटर पर है खनन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-148 लगभग 500 मीटर की दूरी पर एवं कच्चा मार्ग एवं नाला 100 मीटर की दूरी पर है जबकि लीज स्वीकृति पत्र में आवेदित क्षेत्र से नदी नाला 01 किलोमीटर, रोड़ लगभग 400 मीटर, 500 मीटर पर आबादी तथा हाईटेंशन लाईन 80 मीटर पर है अतः इनकी संरक्षण योजना सही दूरी के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. लीज आर्डर नं. 498 दिनांक 18/4/22 कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जिसमें लिखा है कि आवेदित क्षेत्र में 02 निस्तार के तालाब बनाये गये हैं तथा आवेदित सर्वे नं. में गौशाला हेतु पूर्व में प्रस्तावित की गई है अतः परियोजना प्रस्तावक कलेक्टर आफिस से यह लिखित में प्राप्त करें कि खसरा क्रमांक 340 पर खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा इसका वर्तमान उपयोग निस्तार तालाब एवं गौशाला हेतु नहीं है।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. शासकीय भूमि (यदि) का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

8. Case No 9179/2022 M/s Shri Balaji Granite, Partner, Smt. Renu Singhal, 502, Satyam Residency Tower, Alkapuri Tirha, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.584 ha. (38475 Cum per annum) (Khasra No. 38/1, 51/Min-2k, 51/Min-2kha, 52/Min-2k, 52/Min-2kha, 52/1/Min-1), Village - Berja Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 38/1, 51/Min-2k, 51/Min-2kha, 52/Min-2k, 52/Min-2kha, 52/1/Min-1), Village - Berja Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) 1.584 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9788 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 14.446 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के अंदर से उत्तर दिशा में एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस रोड़ का उपयोग आस-पास स्थित अन्य खदानों द्वारा किया जाता है तथा चूंकि हमारी लीज अभी कार्यरत नहीं हुई है इसलिए अस्थाई रूप से इसका उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। जब हमारी लीज कार्यशील हो जायेगी तो अन्य खदानों द्वारा उपलब्ध दूसरे वैकल्पिक मार्ग का उपयोग परिवहन हेतु किया जायेगा। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के अंदर से उत्तर दिशा में एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके उपयोग आस-पास स्थित अन्य खदानों द्वारा किया जाता है अतः वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. शासकीय भूमि (यदि) का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

9. Case No 9169/2022 Smt. Pooja Jaiswal, Owner R/o 125, Gandhi Nagar, Dist. Ratlam, MP - 457001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 167), Village - Sarwani Khurd, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 167), Village - Sarwani Khurd, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 3.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4823 दिनांक 24/09/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर नदी, उत्तर दिशा में दो मौसमी नाले 105 व 60 मीटर पर तथा तालाब 120 मीटर पर उत्तर दिशा में है इसी प्रकार दक्षिण पूर्व दिशा में 180 मीटर पर आबादी है अतः 20 मीटर का सेट बैक छोड़ा जाना होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण में ही 20 मीटर का सेट बैक छोड़ दिया गया है तथा जलीय निकाय की सुरक्षा हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा । इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के पूर्व में लीज के अंदर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिससे भी 50 मीटर का सेट बैक छोड़ा जाना होगा एवं इसी सेट बैक में आबादी के कारण छोड़ा जाने वाला 20 मीटर का सेट बैक शामिल होगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र में 01 पेड़ बबूल का लगा है

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

जो काटा जायेगा तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ आंवटित क्षेत्र के पूर्व में लीज के अंदर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिससे भी 50 मीटर का सेट बैक छोड़ते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-12,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पूर्व में लीज मौसमी नाला के कारण खनन क्षेत्र में 50 मीटर का सेट बैक (नॉन माईनिंग जोन) छोड़ा जाये ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.07 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
	ग्राम सरवनी खुर्द के आंगनवाड़ी केंद्र में बर्तन व पोषण आहार का वितरण एवं अन्य उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी ।	25,000/-
	योग	25,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3610 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि ।	1200 पौधे
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग तक (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आम, कदम आदि ।	500 पौधे

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

3	ग्राम बिबरौद के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला, कचनार, बरगद, पीपल आदि।	100 पौधे
4.	ग्राम बिबरौद के गौ शाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पीपल, सप्तपर्णी, चिरोल, करंज (चारा प्रजाति के ...) आदि।	210 पौधे
5.	ग्राम बिबरौद के मुक्ति धाम परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- बरगद, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पीपल, सप्तपर्णी, चिरोल, करंज आदि।	400 पौधे
6.	ग्राम बिबरौद के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, जामुन, अमरुद, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	1200 पौधे
कुल			3610 पौधे
दूसरे वर्ष मृत पौधों का पुर्नस्थापना किया जावेगा और लीज अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा।			

10. Case No 9170/2022 Shri Rahul Jaiswal, Owner, 125, Gandhi Nagar, Dist. Ratlam, MP - 457001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (12000 Cum per annum) (Khasra No. 167), Village - Sarwani Khurd, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 167), Village - Sarwani Khurd, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 29/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4824 दिनांक 24/09/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 110 मीटर पर नदी, उत्तर दिशा में दो मौसमी नाले 210 व 220 मीटर पर तथा तालाब 300 मीटर पर उत्तर दिशा में है इसी प्रकार दक्षिण पूर्व दिशा में 170 मीटर पर आबादी है अतः 30 मीटर का सेट बैक छोड़ा जाना होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 30 मीटर का सेट बैक छोड़ दिया जायेगा तथा जलीय निकाय की सुरक्षा हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ आंवटित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में लीज से 170 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः 30 मीटर का सेट बैक छोड़ते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-12,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. दक्षिण पूर्व दिशा में 170 मीटर पर आबादी है अतः 30 मीटर का सेट बैक (नॉन माईनिंग जोन) छोड़ा जाये।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.35 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख :-

	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
	ग्राम बिबरौद के आंगनवाड़ी केंद्र में बर्तन व पोषण आहार का वितरण एवं अन्य उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी	25,000/-
	योग	25,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2470 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	---	---------------------	------------------------

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, आचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल, आदि।	880
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग तक (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आम, कदम आदि।	300
3	ग्राम सरवनीखुर्द के नजदीक स्थित मुक्ति धाम परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- बरगद, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पीपल, सप्तपर्णी, चिरोल, करंज आदि। 01 मीटर से अधिक के पौधें।	250
4.	ग्राम सरवनीखुर्द के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवलाए कचनार, बरगद, पीपल आदि। 01 मीटर से अधिक के पौधें।	100
5.	रतलाम में स्थित केंद्रीय विद्यालय के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंजए कचनार, चिरोल सप्तपर्णी, पीपल, नीम आदि। 01 मीटर से अधिक के पौधें।	140
6.	ग्राम सरवनीखुर्द के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	800
कुल			2470
मृत पौधों का बदलाव एवं रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक।			

11. Case No 9171/2022 Shri Kishan Singh Chouhan, Owner, Village - Sada, Tehsil - Bahoribandh, Dist. Katni, MP - 483331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

प्रकरण आज दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

12. Case No 9172/2022 M/s M.P.Housing & Infrastructure Development Board, Shri Pawan Dabhade, Executive, Division No. 06, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Dist. Bhopal, MP - 462003 Prior Environment Clearance for Proposed Multi Storey Residential Building "Tulsi Green Tulsi Tower 2" at Village - Shahpura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, MP, Total Plot area 7733.03 Sqm (1.91 Acres), Proposed Builtup Area 44606.90 Sqm. (Cat. 8(a) Building and Construction Project) Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Multi Storey Residential Building "Tulsi Green Tulsi Tower 2" at Village - Shahpura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, MP, Total Plot area 7733.03 Sqm (1.91 Acres), Proposed Builtup Area 44606.90 Sqm.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Construction of Proposed Multi Storey Residential Building "Tulsi Green Tulsi Tower 2" at Village - Shahpura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, M.P. Hence, prior requires EC from SEIAA before initiation of activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri G. K. Mishra from M/s. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.) on behalf of PP, wherein during presentation Following are the salient features of the project:

- Proposed Multi-Storey Residential Building “Tulsi Green Tulsi Tower 2” by M/s Madhya Pradesh & Infrastructure Development Board which is to be developed at Village – Shahpura, Tehsil – Huzur & District – Bhopal and State – Madhya Pradesh.
- The total plot size for the project is 7,733.03 m² (1.91 Acres). The project will be developed for Residential Tower
- The Proposed project consists of Multiunit Residential Towers.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

- The total Built up Area is 44,606.90 m², which is less than 1,50,000.00 m² therefore, the project comes under schedule 8(a); category B as per the EIA Notification 14th September, 2006.
- **AREA STATEMENT**

S. No	Particulars	Total (m ²)
1.	Total plot area	7,733.03 Sq.mtr. (1.91 Acres)
3.	Proposed Built up Area	44,606.90 Sq. mtr.
5.	Permissible Ground Coverage (Residential)	30% = 2319.90 Sq. mtr.
6.	Provided Ground Coverage (Residential)	1503.08 Sq. mtr. = 19.50%
7.	Permissible Recreational Ground	11%=850.63 Sq. mtr.
8.	Provided Recreational Ground	1209.11 Sq. mtr. = 15.63%(A+B)
	Open Space on Ground (A)	819.84 Sqm
	Open Space on Podium (B)	389.27 Sqm
10.	Proposed FAR	21,265.8325 sqm
11.	Proposed NON-FAR	23,341.0675 sqm
TOWER 2		
	Basement floor	Sqm 379.99 1.0 379.99
	Ground floor	Sqm 275.74 1.0 275.74
	Podium floor	Sqm 568.36 1.0 568.36
	Landscape floor	Sqm 460.40 1.0 460.40
	Typical floor - 1st-3rd, 5th-10th, 12th-17th, 19th-21st	Sqm 489.99 18.0 8,819.87
	Refuge floor - 4th, 11th, 18th	Sqm 489.99 3.0 1,469.98
	Terrace floor	Sqm 116.13 1.0 116.13
	LMR	Sqm 0.00 1.0 0.00
	Total	Sqm 12,090.47
TOWER 1		

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

Basement floor	Sqm	588.78	1.0	588.78
Ground floor	Sqm	290.94	1.0	290.94
Podium floor	Sqm	621.64	1.0	621.64
Landscape floor	Sqm	599.03	1.0	599.03
Typical floor - 1st-3rd, 5th-10th, 12th-17th, 19th-21st	Sqm	515.66	18.0	9,281.93
Refuge floor - 4th, 11th, 18th	Sqm	515.66	3.0	1,546.99
Terrace floor	Sqm	116.13	1.0	116.13
LMR	Sqm	0.00	1.0	0.00
Total	Sqm			13,045.45

TOWER 3				
Basement floor	Sqm	419.06	1.0	419.06
Ground floor	Sqm	286.08	1.0	286.08
Podium floor	Sqm	578.71	1.0	578.71
Landscape floor	Sqm	460.40	1.0	460.40
Typical floor - 1st-3rd, 5th-10th, 12th-17th, 19th-21st	Sqm	489.99	18.0	8819.87
Refuge floor - 4th, 11th, 18th	Sqm	489.99	3.0	1469.98
Terrace floor	Sqm	116.13	1.0	116.13
LMR	Sqm	0.00	1.0	0.00
Total	Sqm			12150.23

PROJECT DETAILS

PROJECT FEATURES	DESCRIPTION
Total Estimated Population	1,081 persons (Residents, Staff & Visitor)
Total Estimated Water Requirement Construction Phase Operation Phase	378.06 KLD (Agency: Private Water Tanker) 123.425 KLD (Fresh Water = 78.530 KLD) (Agency: Municipal corporation)
Total Estimated Wastewater Generation Construction Phase	5.4 KLD 115.542 KLD

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

Operation Phase	
Power Demand Power Back-up DG Set	1250 kVA 250 kVA (1 x 250 kVA)
Source of Power	Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)
Solid Waste Generation C&D Waste	0.475 TPD Approx. 250 M ³ (There are some temporary structure of social Justice & Disabled welfare Department available at site which have been resettled in new building constructed by MPHIDB al Link road 3.)
Parking Facilities Required Proposed	234 268
Project Cost	Rs. 200.00 Crores

PROJECT DETAILS

S. No.	Particulates	Tower 01	Tower 02	Tower 03
1.	3 BHK	0	21	21
2.	BHK-R-2	0	3	3
3.	BHK-R	3	0	0
4.	4 BHK	0	18	18
5.	BHK – T1	39	0	0

- Currently the project site is almost a flat land.
- No water body or drains passes through the project site.
- Leveling of the site is so done to maintain the natural gradient.
- It will not have any adverse effect on the surrounding of the project site.
- Ground water depth of project regime is around 40-45 meters gbl.
- During construction phase, water requirement is being met by Private water tanker.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

- During operation phase, ground water will be extracted to meet the water demand of the occupants.
- The Ground water level will be maintained by constructing 1 number of Rain Water Harvesting Tank at project site.
- Ground water will not be used for the construction purposes.
- The Average Annual of rainfall has been considered as 1126.7 mm (1.126 m). The rainwater harvesting will be done for rooftop areas through percolation wells. The harvested water will be used for artificial recharge and will not be stored. A network of percolation wells has been proposed for artificial recharge of ground water.
- On the completion of rooftop rainwater harvesting, road runoff rainwater harvesting, open land area rainwater harvesting, the total recharge potential of the proposed project would be as under:
 - ✓ After the completion of the project and rainwater harvesting structures, there will be total ground water recharge would be 21455.897 m³/ annum. Proposed recharge potential to be created by the project would improve ground water regime of the area and would contribute to positive groundwater environment.
- **C & D WASTE**
 - ✓ Demolition of 3 TO 4 Shaded temporary structures where Approx. 250 M³ . C&D Waste including constructed material, Bricks, Tin sheets, iron rods and angle will be generated .
 - ✓ (There are some temporary structure of social Justice & Disabled welfare Department available at site which have already been Shifted & resettled in new building constructed by MPHIDB at Link road 3.)
 - ✓ All C& D Waste will be disposed through qualified vendor. The conditions of tender is to maximum reuse of the waste like Bricks and tin shades at site itself. Waste like iron rods, angles will be sold through vendor. All other building inert material waste will be disposed off at the MPH
- **Energy Conservation measures**
 - ✓ Maximum use of natural lighting through architectural design.
 - ✓ All common spaces including street lights (where there is no use of light for reading purposes), will be of “LED. All internal lighting will be BEE star rated and solar lit, at least to an extent of 25%.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

- ✓ Integration of automated system to operate electrical equipment as per load requirement to save energy
 - ✓ Use of solar energy for street lighting.
 - ✓ Appropriate Design to shut out excess heat and gain loss.
- **Green belt/Green cover and the Landscape plan**
 - ✓ For the project, Greenery will be provided in 1209.11 sqm (@ 15.8% of the plot area), which will enhance the beauty of the site and help combat air and noise pollution.
 - ✓ A diverse variety of indigenous evergreen and ornamental trees would be planted.
 - ✓ The plant species will be selected on the basis of Urban Standard Plantation norms and CPCB guidelines.

During presentation it was observed that in the Google image of the area that within project has some sheds and huts are existed moreover some matured big trees are also existed. PP stated that there are some temporary structure of Ministry of Social Justice & Disabled Welfare Department (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग) Govt. of MP available at site which have been resettled in new building constructed by MPHIDB at Link road 3. This project is considered under re-densification of the area. PP further stated that there are 35 nos. of tree in the project site these and all are proposed for felling for which they have taken permission from the competent authority. During presentation committee asked/suggested to plan for take Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) / Indian Green Building Council (IGBC) top rating . The Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

- Commitment/ proposal from PP for three star GRIHA/ IGBC rating.
- Electric load calculation considering ACs and other power consuming modern households' apparatus in all rooms.
- Sun path and wind load evaluation for proposed building and commitment that minimum 06 hours sun light will be available with the current design.
- Revised EMP as suggested by the committee considering proposal for habitat development in Van Vihar, Bhopal.
- Design criteria for providing 02 lifts in a tower and designed maximum waiting time at a floor for residents.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

PP vide letter dated 29.05.2022 has submitted the revised plantation species details which was placed before the committee. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Multi Storey Residential Building "Tulsi Green Tulsi Tower 2" (Total Plot Area = 7733.0 sqm, (1.91 ha.) , Proposed Total Built up Area = 44,606.90 sqm) at Village - Shahpura, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP). Cat. 8(a) subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 01 Diesel power generating sets 250 kVA (1 x 250 kVA) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG sets 250 kVA (1 x 250 kVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be

used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 123.425 KLD out of which 78.530 KLD is fresh water requirement and 115.572 KLD KLD will be the total waste water generated 44.895 KLD water will be used for flushing,
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 11% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 03 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits 21455.897 m³/ annum. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBBR based STP (Capacity - **125 KLD**). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 125 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public

Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher.

Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. Total waste 0.475 TPD, and Approx. out of which Total Biodegradable 55% of total waste - 0.258 TPD & Total Non-Biodegradable 45% of total waste 0.2235 TPD and demolition of 3 TO 4 Shaded temporary structures where Approx. 250 m³ C&D Waste including constructed material, Bricks, Tin sheets, iron rods and angle will be generated. These all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

VII. Green Cover

- i. For the project, Greenery will be provided in 1209.11 sqm (@ 15.8% of the plot area), which will enhance the beauty of the site and help combat air and noise pollution with following species :

S. No.	Common Name	Numbers
1.	Shade Loving (Heuchera)	70
2.	Golden Ficus	10
3.	Dwarf Champa	20
4.	Bottle Palm	10
5.	Areca Palm	20
6.	Ashoka	20
7.	Neem	10
8.	Ornamental Bamboo	50
9.	Raj Grass (Green)	150 sqm
10.	Seasonal Flower bearing Plants	100

- ii. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

- a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
 - iii. Total proposed Parking's arrangement for 268 ECS (in which 109 ECS for Basement parking, 81 for ECS for ground and 78 ECS for podium.
 - iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP& Corporation Environment Responsibility

- i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 228.210 Lakhs as capital cost and Rs. 15.485 Lakhs as recurring cost for construction phase and operation phases. Moreover PP has also proposed adaptation of wild animals in the Van Vihar, Bhopal include Rs. 5.0 lakh in the above cost under EMP.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2022

Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

13. Case No 9178/2022 Shri Sudeep Singh Thakur, Village - Dhuradakala, Tehsil - Jawar, Dist. Sehore, MP - 466221 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10260 Cum per annum) (Khasra No. 145/1), Village - Dhuradakala Tehsil - Jawar, Dist. Sehore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 145/1), Village - Dhuradakala Tehsil - Jawar, Dist. Sehore (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minalable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केंचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

574वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.